भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3081

उत्तर देने की तारीख-20/08/2025

स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता की जाँच के लिए एआई-आधारित तंत्र

3081 **श्री एस. निरंजन रेड्डी:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता और पोषण के स्तर की जांच करने के लिए कोई एआई-आधारित तंत्र का आरम्भ करने की मंशा रखती है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या मंत्रालय देश भर में भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट भामरागढ़ के अंतर्गत गढ़चिरौली, महाराष्ट्र में विकसित की गई एआई मशीन के उपयोग का विस्तार करने का विचार रखता है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों(यूटी) के साथ साझेदारी में कार्यान्वित सबसे महत्वपूर्ण अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजना में से एक है जिसमें सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बाल वाटिका (कक्षा I से ठीक पहले) और कक्षा I से VIII में पढ़ने वाले सभी बच्चों को गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन प्रदान करना शामिल है। इस योजना में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 10.35 लाख से अधिक स्कूलों में लगभग 11 करोड़ बच्चों को शामिल किया गया है। योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित पात्र बच्चों को गर्म पका हुआ और पोषक भोजन प्रदान करने की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, पीएम पोषण योजना के लिए भारत सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा बजट आवंटन का हिस्सा 12,500 करोड़ रुपये है जो कि साझाकरण पद्धति के अनुसार यह करीब 8,500 करोड़ रुपये है, जिसमें रसोइया-सह-सहायकों को मानदेय और पूरक पोषण मदों के लिए अतिरिक्त निधियां शामिल है।

भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न आवंटन 24.15 लाख मीट्रिक टन है जिसकी लागत लगभग 9000 करोड़ रुपये है। इस प्रकार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएम पोषण योजना हेतु समग्र आवंटन 30,000 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें भारत सरकार द्वारा किया गया 21,500 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन भी शामिल हैं।

भारत सरकार ने इस योजना के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन परोसा जाना सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने की सलाह दी गई थी। ये दिशानिर्देश आधिकारिक वेबसाइट https://pmposhan.education.gov.in पर उपलब्ध हैं। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) और शिक्षकों के माध्यम से गर्म भोजन की गुणवत्ता, खरीद तंत्र, भोजन की तैयारी, रसोइया-सह-सहायकों का प्रशिक्षण, खाद्य नमूनों का अनिवार्य परीक्षण, सभी जिलों में कम से कम 20 स्कूलों या 2% स्कूलों (जो भी अधिक हो) में सामाजिक लेखा परीक्षा आदि का प्रावधान है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के मापदंडों को पूरा करते हुए सर्वोत्तम उपलब्ध गुणवत्ता का खाद्यान्न उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रत्येक ज़िले के ज़िला मजिस्ट्रेट को खाद्यान्न की गुणवत्ता की जाँच करनी होती है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, पर्यटन मंत्रालय (होटल प्रबंधन संस्थानों और खाद्य शिल्प संस्थानों के माध्यम से), एफएसएसएआई, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की सहकार्यता से सीसीएच को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिया गया है कि वे रसोइया-सह-सहायकों के बीच पाक-कला प्रतियोगिताएं आयोजित करें ताकि उन्हें विविध और पौष्टिक भोजन पकाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पाक-कला प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं और विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान करते हैं।

महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग ने बताया है कि पीएम पोषण योजना के तहत भोजन की गुणवत्ता और पोषण स्तर की निगरानी के लिए एआई-आधारित तंत्र को जनजातीय कल्याण मंत्रालय के तहत टोडसा गांव, भामरागढ़ (गढ़चिरौली) में स्थित एक आश्रम स्कूल के लिए प्रायोगिक आधार पर लागू किया गया है और इसकी निगरानी एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, भामरागढ़ द्वारा की जाती रही है। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश राज्य ने भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और भोजन तैयार करने, वितरण तथा स्कूलों की समग्र स्वच्छता की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री पोषण योजना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को एकीकृत किया है। भारत सरकार सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को प्रधानमंत्री पोषण योजना के प्रभावी और सफल कार्यान्वयन के लिए नवीन पद्धति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित नवीनतम तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

*****